खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता

*141. श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामसेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हेडा :
श्री म० चं० बरुग्रा :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री सेझियान :
श्री कन्डप्पन :
श्री राजाराम :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस दशक के अन्त तक खाद्यान्न में आत्म निर्भर होने के घोषित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, राज्य सरकारों के परामर्श से आवश्यक कदम उठाने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). भारत सरकार ने एक हाई यील्डिंग वरायटीज प्रोग्राम बनाया है जो बीजों की अच्छी उपज वाली किस्मों पर सुधरे तरीकों को प्रयोग में लाते हुए चुने हुए क्षेत्रों में शुरू किया जा रहा है । प्रस्ताव यह है कि लगभग 32.5 मिलियन एकड़ क्षेत्र में धान की अच्छी उपज की किस्में (ताईचुंग नेटिव 1, ताईचुंग 65, ताईवान 3 तथा ए० डी० टी० 27), गेहूं की मैक्सीकन किस्में और मक्की, ज्वार तथा बाजरा की संकर किस्में उगाई जायें । आशा है इस-कर्यक्रम द्वारा 25.5 मिलियन टोन्स खाद्यान्नों की अतिरिक्त उपज होगी । इस कार्यक्रम के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों की आवश्यक मात्रा का प्रबन्ध किया जा रहा है । और बीज की आवश्यक मात्राओं की वृद्धि के लिए भी प्रबन्ध किए जा रहे हैं । यह कार्यक्रम उन सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त है जो बड़ी तथा माध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और सुधरे बीजों, उर्वरकों आदि के वितरण के लिए समस्त देश में बनाये गये हैं ।

आशा है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद देश में 1970—71 तक खाद्यान्नों का कोई नेट आयात नहीं होगा ।

State Trading in Food

*142. **Dr. L. M. Singhvi:**
Shri R. S. Pandey:
Shri Ravindra Varma:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether Government have assured financial and other assistance to such States as are willing to undertake State trading in food;

(b) if so, the response of the State Governments; and

(c) the financial and administrative implications of such an assistance?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri